

{2015} 1 S.C.R. 152 152.

कार्यकारी अधिकारी, और आदि।

आवाज।

जी। ए। कुमारस्वामी (डी) द्वारा एलआरएस।

। (सिविल अपील सं। 8577 of 2014) JANUARY 19, 2015।

[एम। वाई "। EQBAL और KURIAN JOSEPH, JJ].

अपील दायर करने में विलंब:-अपील दायर करने में 1373 दिनों की विलंब-मुकदमा दायर करने के लिए मुकदमा दायर करने के लिए मुकदमा और प्रथम प्रतिसाद ट्रायल कोर्ट द्वारा दायर की गई सूट भूमि पर मुकदमा खारिज कर दिया-प्रथम प्रतिवादी ने अपील दायर की-जिसके बाद अपीलकर्ता द्वारा कोई कदम नहीं उठाया गया-4 साल बाद, अपीलकर्ता ने निर्णय और डिक्री की प्रमाणित प्रति के लिए आवेदन किया-इसके बाद, दूसरी अपील दायर की गई, जिसमें देरी के लिए अनुकंपा के लिए आवेदन के साथ-उच्च न्यायालय ने विलंब को अस्वीकार कर दिया-विलंबित, विलंबित अपील: विलंबित, जो भी हो सकता है अगर सरकारी अधिकारियों या सरकारी कर्मचारियों की ओर से देरी को हराने के प्रयास पर निंदा की जाती है।

अपील को स्वीकार करने और मामले को उच्च न्यायालय में भेजने के लिए, न्यायालय

HELD: 1। देरी केवल संबंधित समय पर पंचायत के कार्यकारी अधिकारी की ओर से जानबूझकर चूक के कारण हुई। यदि अदालत को आश्चस्त किया जाता है कि सरकारी अधिकारियों या लोक सेवकों की ओर से देरी के कारण न्याय को पराजित करने का प्रयास किया गया था, तो अदालत को, बड़े जनहित के मद्देनजर, इस तरह की स्थितियों में एक उदार दृष्टिकोण रखना चाहिए, देरी को निंदा करें, जो भी भारी हो सकता है देरी हो सकती है, और योग्यता के आधार पर मामले का फैसला किया है। दूसरी अपील दायर करने में 1373 दिनों की देरी की निंदा की जाती है। [पारस 3,4 और 5] [154-ई, जीएच-एच; 155-ए]

152 152.

कार्यकारी अधिकारी, ANTIYUR TO PANCHAYAT 153

वी। जी। ए। कुमारस्वामी (डी) द्वारा एलआरएस।

नागालैंड राज्य बनाम। कीपरें ए और ओआरएस। (2005) 3 एससीसी

752: 2005 (3) एससीआर 108-पर भरोसा किया। केस लॉ रेफरेंस: 2005 (3) एससीआर 108 पैरा 5 पर निर्भर था।

नागरिक अपील सं।

2014 का 8577।

C.M.P में मद्रास में उच्च न्यायालय के 17.04.2006 के निर्णय और आदेश से। नहीं। 2006 के 4874 में S.A. SR No. 2006 का 876।

WITH

एल. एल. नहीं। 2014 के 2 2014 के 2

अपीलकर्ता के लिए आर। नेदकुमारन।

V.N. सुब्रमण्यम, उत्तरदाताओं के लिए रेवथी राघवन।

न्यायालय का निर्णय द्वारा दिया गया था।

KURIAN, जे. 1। A.S. 14.11.2000 के फैसले के खिलाफ अपील दायर करने में 1373 दिनों की देरी की निंदा करने के लिए उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश से अपीलकर्ता व्यथित है। अधीनस्थ न्यायाधीश, भावनगर, इरोड जिला, तमिलनाडु की फाइल पर 1999 का 108। यहाँ पहली प्रतिवादी ने O.S. नहीं। सूट भूमि की घोषणा और कब्जे के लिए अतिरिक्त जिला मुंसिफ कोर्ट, भावनगर, तमिलनाडु की फाइल पर 1992 का 267। सूट में प्रतिवादी ग्राम पंचायत ने दावा किया कि सूट भूमि नाथम पोरंबोक है और शीर्षक के कब्जे और रिकॉर्ड पंचायत के नाम पर हैं। ट्रायल कोर्ट ने 11.07.1997 के फैसले को खारिज कर दिया। शिकायतकर्ता-प्रथम प्रतिवादी ने यहां A.S. No. 1999 का 108। अपील की अनुमति दी गई थी और 14.11.2000 के फैसले से मुकदमा कम हो गया था;।

2। ऐसा प्रतीत होता है, संबंधित समय में पंचायत के कार्यकारी अधिकारी द्वारा कोई कदम नहीं उठाया गया था। जब कार्यकारी अधिकारी, दूसरी अपील दायर करने के समय, कार्यवाही के बारे में पता चला, जब बेदखली के लिए कदम उठाए गए थे, तो उन्होंने तुरंत कदम उठाए और निर्णय और डिक्री की प्रमाणित प्रति के लिए 26.10.2004 को एक आवेदन दायर किया। 15.12.2004 को जारी किए गए थे, और आवश्यक मंजूरी प्राप्त करने और अन्य प्रक्रियात्मक औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद, दूसरी अपील 05.01.2005 को विलंब के लिए आवेदन के साथ दायर की गई थी। लगाए गए आदेश से, उच्च न्यायालय ने देरी की निंदा करने से इनकार कर दिया। उच्च न्यायालय के अनुसार, देरी को ठीक से समझाया नहीं गया है। लगाए गए आदेश में यह भी देखा गया है कि यद्यपि प्रमाणित प्रतियां 15.12.2004 को जारी की गई थीं, दूसरी अपील केवल 05.01.2005 को दायर की गई है और उस देरी के लिए भी कोई स्पष्टीकरण नहीं है।

3। 12.12.2006 को अपीलकर्ता की ओर से दायर अतिरिक्त हलफनामे में, इस न्यायालय के संज्ञान में लाया गया कि श्री के। रामासामी, जो संबंधित समय में पंचायत के कार्यकारी अधिकारी के रूप में काम कर रहे थे, को सेवा से निलंबित कर दिया गया था। भ्रष्टाचार के आरोपों पर 12.07.2002। जैसा कि हो सकता है, अभिलेखों के माध्यम से जाने के बाद और दोनों पक्षों के वकील को सुनने के बाद, हम संतुष्ट हैं कि प्रासंगिक समय पर पंचायत के कार्यकारी अधिकारी की ओर से जानबूझकर चूक के कारण देरी हुई। जो और प्रक्रिया में शामिल हैं, वह बिल्कुल स्पष्ट नहीं है।

4। जैसा कि नागालैंड राज्य में इस न्यायालय द्वारा आयोजित किया गया था। लीपर ए और अन्य', अदालत को देरी के लिए एक आवेदन पर विचार करते हुए हमेशा न्याय-उन्मुख दृष्टिकोण रखना चाहिए। यदि अदालत को आश्वस्त किया जाता है कि सरकारी अधिकारियों या लोक सेवकों की ओर से देरी के कारण न्याय को पराजित करने का प्रयास किया गया था, तो अदालत को, बड़े जनहित के मद्देनजर, इस तरह की स्थितियों में एक उदार दृष्टिकोण रखना चाहिए, देरी को निंदा करें, जो भी भारी हो सकता है देरी हो सकती है, और योग्यता के आधार पर मामले का फैसला किया है।

1। (2005) 3 एससीसी 752।

कार्यकारी अधिकारी, ANTIYUR TO PANCHAYAT 15515

"C v I G ARUMUMUGAM (D) LRS द्वारा। [KURIAN JOSEPH, जे.]

5। तदनुसार, हमने दूसरी अपील दायर करने में 1373 दिनों की देरी के लिए लगाए गए आदेश को अलग रखा। कानून के अनुसार आगे के विचार के लिए मामले को उच्च न्यायालय में भेज दिया जाता है। इंटरलोक्यूटरी एप्लिकेशन नं। 2014 के 2 के अनुसार निपटाया जाता है।

6। उपरोक्त के रूप में अपील की अनुमति है। लागत के रूप में कोई आदेश नहीं है।
।

देविका गुजरात अपील की अनुमति दी और उच्च न्यायालय को भेज दिया गया।